THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) The percentage of capacity utilisation of Hindustan Shipyard during 1991-92 was 38%.

(b) The overall loss incurred during 1991-92 was Rs. 103·74 crores (provisional).

(c) The main reasons for losses are :—

(1) Cost-Price gap.

(2) Low productivity.

(3) Time over-runs in completion of ships.

(4) Huge interest burden on borrowings from banks etc. to finance working capital requirements.

(d) A proposal for revival of the Shipyard keeping in view the latest changes in the import-export policy of the Government, is under consideration. Another proposal for capital re-structuring of the Shipyard involving conversion of project development loans into equity, waiver of interest etc. is under consideration. Government has recently permitted Hindustan Shipyard Limited to sell three vessels in the open market which had been ordered by Shipping Corporation of India. Voluntary Retirement Scheme has been implemented and so far 851 emlpoyees have opted for retirement.

राष्ट्रीय राजमार्ग 20 और 21 को जोड़ना

2242. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार/जन प्रतिनिधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 20 और 21 को लिंक रोड द्वारा यानी बजौरा कन्डी, जिला कुल्लू मंडी (हिमाचल प्रदेश) से जोड़ने के संबंध में कोई प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां । जनवरी, 1991 में हिमाचल प्रदेश सरकार से केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 20 को राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 21 से जोड़ने के लिए 765.00 लाख रुपए की लागत से कंडी निऔल से होकर गुजरने वाली एक वैकल्पिक सड़क नामतः मंडी-बजौरा के निर्माण के संबंध म एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

(ग) चूंकि , केंद्रीय सरकार सड़क निधि में संसद द्वारा दिनांक 13-5-1988 को पारित संशोधित संकल्प के अनुरूप वस्तुतः अभी तक वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए उपर्युक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु कार्रवाई नहीं की जा सकी ।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा निधियों का कम उपयोग किया जान

2243. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन** :
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मई, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "डी.टी.सी. फैल्स टू यूटिलाइज बजट एलोकेशन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पचवर्षीय योजनावधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के लिए कुल कितना आवंटन किया गया था ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निगम द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई, ; और

(घ) बजट में आवंटित सम्पूर्ण राशि खर्च न किए जाने के क्या कारण थे ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के लिए कुल 93.58 करोड रुपए का आवंटन किया गया था ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने कुल 76.39 करोड़ रुपए की राशि खर्च की ।

(घ) बसों की खरीद के लिए दि०प०नि० द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित न किए जाने के कारण 1989–90 के दौरान खर्च में कमी आई।

National Highways

2244. SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN : Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) the number of National Highways in the country ;

(b) what is the length of each of these Highways ; and

(c) what is the allocation made for the maintanance of National Highways during the current year ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) and (b) There are 76 National Highways in the country. Details of length of these are given in the attached statement. (*see below*)

(c) For current year, the tentative allocation for maintenance of National Highways is Rs. 169·67 Crores.

Statement

S. No.	NH No.	Length in Km. (provisional)
1	2	3
1	1	456
2	1A	663
3	1B	107
4	2	1490
5	3	1161
6	4	1235
7	4A	153
8	4B	27
9	5	1533
10	5A	77
11	6	1645
12	7	2359
13	7A	51
14	8	1428
15	8A	378
16	8B	206
17	8C	46
18	9	791
19	10	403
20	11	582
21	11A	64
22	12	890
23	13	491
24	14	450
25	15	1526
26	16	460
27	17	1269
28	17A	19
29	20	220
30	21	323